

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बर्डजलास श्री अनुराग भार्गव आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

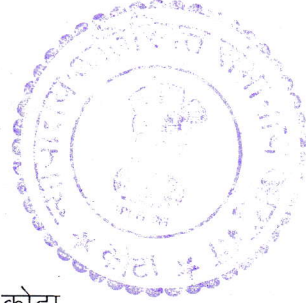
प्रकरण संख्या: 41./2019/अपील/एजआरएक्ट/कोटा

दायरा दिनांक: 9.5.2019

अन्तर्गत धारा: 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उनवान

1. जसवंत सिंह पुत्र स्व0 भवानी सिंह
 2. बजरंग सिंह पुत्र स्व0 भवानी सिंह
 3. श्रीमती कैलाश कंवर पुत्री स्व0 भवानी सिंह
 4. हेमकंवर पुत्री स्व0 भवानी सिंह
 5. श्रीमती सज्जनकंवर पत्नी स्व0 भवानी सिंह
- जाति राजपूत निवासीगण ग्राम खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा



...अपीलार्थी

बनाम

1. श्याम मनोहर पुत्र स्व0 मांगीलाल
 2. दिनेश पुत्र स्व0 मांगीलाल
 3. मोहन बाई पुत्री स्व0 मांगीलाल
 4. श्रीमती कंचनबाई पुत्री स्व0 मांगीलाल
- जाति कलाल निवासीगण ग्राम खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
5. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा।

... रेस्पोजेन्ट

उपस्थित— श्री बी0 सी0 मालवीय अभिभाषक —अपीलार्थी
श्री सत्यनारायण गौतम अभिभाषक—रेस्पोजेन्ट 1 ता 4

::निर्णय::

दिनांक 3.3.2022

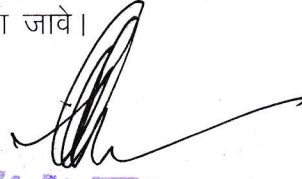
अपीलार्थी ने न्यायालय उप जिला कलक्टर रामगंजमण्डी जिला कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण 136/2015 दावा 183 आरटीए व 136 एलआरएक्ट बउनवान जसवंत सिंह बनाम श्याम मनोहर मे पारित निर्णय दिनांक 27.06.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

- 1 प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलांत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे आरटीए की धारा 183 एवं एलआरएक्ट की धारा 136 के अन्तर्गत वाद पेश कर निवेदन किया प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम खैराबाद मे 3.3 है0 स्थित है उक्त आराजीयात मे से ख0 नं0 2824 रकबा 0. 99 है0 भूमि प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 4 के खाते व कब्जे काश्त की भूमि ख0 नं0 2827 रकबा 04 बीधा से लगी हुई है। प्रतिवादीगण 1 ता 4 द्वारा विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना वादीगण के खाते व कब्जे काश्त की

जिला कोटा राजस्थान
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

भूमि ख० नं० 2824 के करीब डेढ बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है जो बेदखली का पात्र है। सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा नक्शा तरमीम को ध्यान में न रखते हुये मौके की स्थिति से भिन्न जाकर वादीगण को नुकसान पहुंचाने की उद्देश्य से गलत नक्शा ट्रेस का अंकन कर दिया। जबकि सेटलमेंट विभाग को नक्शा ट्रेस में परिवर्तन करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः वाद स्वीकार कर प्रति० 1 ता 4 को वादी के स्वामित्व की आराजी ख० नं० 2824 से बेदखल कर कब्जा वादीगण को संभलाया जावे तथा नक्शा ट्रेस में आराजीयात के रकबे अनुसार परिवर्तन किया जावे।

- 2 अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद लोक अदालत रखते हुये अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27.6.2017 के द्वारा वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये डिक्री कर दिया।
- 3 अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय एवं डिक्री 27.6.2017 में धारा 136 एलआरएक्ट की प्रार्थना पर कोई आदेश पारित नहीं कर रेस्पो० को अतिचारी मानते हुये भूमि की पैमाईश कर बेदखल के आदेश पारित किया जबकि नक्शा ट्रेस में खातेदारी की भूमि के रकबा अनुसार परिवर्तन नहीं किया जावेगा तब तक प्रतिवादी को उसके द्वारा अतिक्रमण की गई आराजी से कैसे बेदखल किया जावेगा वर्णित कर पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 27.6.2017 से व्यथित होकर अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में पेश की गई जिसे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा धारा 136 एलआरएक्ट के तहत उपखण्ड अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं होने से अपील मेन्टेनेबल नहीं होने से दिनांक 27.6.2017 को खारिज कर अपील सक्षम न्यायालय में पेश करने के लिये अपीलांत स्वतंत्र होना वर्णित किये जाने पर अपीलांत द्वारा अपील प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद के अधि० के साथ इस आशय की न्यायालय हाजा में पेश की गई कि अपीलांत के खाते की आराजी ख० नं० 2824 रकबा 0.90 है० है जो 5 बीघा 11 बिस्वा होती है जिसे नक्शा ट्रेस 0.71 है० दर्शित किया है जो मौके पर 0.19 है० कम है। इसी प्रकार रेस्पो० के खाते की भूमि खसरा सं० 2827 का रकबा 0.56 है० है लेकिन नक्शा ट्रेस के मुताबिक 0.75 है० बैठता है जो 0.19 है० ज्यादा है अतः ख० नं० 2824 की पश्चिमी मेड के सहारे पट्टी मौजूदा नक्शा ट्रेस से तरमीम कर हटा दी जाती है एवं खसरा सं० 2824 के उत्तरी पश्चिमी की तरफ तरमीम कर 2837 की पूर्वी मेड तक तरमीम कर बना दी जाती है तो ख० सं० 2824 का रकबा नक्शों में 0.90 है० एवं खसरा सं० 2827 का रकबा नक्शों में 0.56 है० बैठ जाता है जो खातेदारों के खाते में दर्ज भूमि मुताबिक सही हो जाता है लेकिन इन तथ्यों पर गौर न करते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने नक्शा ट्रेस में कोई आदेश पारित नहीं कर कानूनी त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.6.2017 निरस्त कर धारा 136 एलआरएक्ट पर विचार कर उचित निर्णय पारित करने की इस्तदुआ की गई।
- 4 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो० को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण में बहस अभिभाषक अपीलांत एवं रेस्पो० अभिभाषक सुनी गई।
- 5 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलांत के खाते की आराजी ख० नं० 2824 रकबा 0.90 है० है जो 5 बीघा 11 बिस्वा होती है जिसे नक्शा ट्रेस 0.71 है० दर्शित किया है जो मौके पर 0.19 है० कम है। इसी प्रकार रेस्पो० के खाते की भूमि खसरा सं० 2827 का रकबा 0.56 है० है लेकिन नक्शा ट्रेस के मुताबिक 0.75 है० बैठता है जो 0.19 है० ज्यादा है अतः ख० नं० 2824 की पश्चिमी मेड के सहारे पट्टी मौजूदा नक्शा ट्रेस से तरमीम कर हटा दी जाती है एवं खसरा सं० 2824 के उत्तरी पश्चिमी की तरफ तरमीम कर 2837 की पूर्वी मेड तक तरमीम कर बना दी जाती है तो ख० सं० 2824 का रकबा नक्शों में 0.90 है० एवं खसरा सं० 2827 का रकबा नक्शों में 0.56 है० बैठ जाता है जो खातेदारों के खाते में दर्ज भूमि मुताबिक सही हो जाता किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर नहीं किया तथा धारा 136 एलआरएक्ट के संबध में कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील स्वीकार कर निर्णय/डिक्री 27.6.2017 निरस्त कर प्रा० पत्र धारा 136 के संबध में उचित निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया जावे।


 दिनांक २० मार्च २०१७

- 6 रेस्पों के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पों अपने खाते की आराजी पर काबिज है अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है।
- 7 हमने पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण बहस पर मनन किया। हमने सर्वप्रथम प्रा० पत्र धारा 5 मियाद का अवलोकन किया। अपीलांत ने अपने प्रार्थना पत्र में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वे उचित प्रतीत होते हैं। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाता है।
- 8 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री दिनांक 27.6.2017 का अवलोकन किया गया अपीलांत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 136 एवं धारा 183 राज० काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश किया था जिसमें वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा संभलाने एवं मूल नक्शे में संशोधन की प्रार्थना की थी। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी आंशिक रूप से स्वीकार कर बेदखली की डिक्री पारित की है। अपीलांत ने अपील में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि नक्शा ट्रेस में संशोधन के बावत धारा 136 एलआरएक्ट में कोई सहायता अधीनस्थ न्यायालय ने प्रदान नहीं की है ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को अतिचारी मानते हुये बेदखल किये जाने संबंधी आदेश की पालना नहीं हो सकती। इस क्रम में हमारा विनम्र मत है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील निर्णय में प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट में वर्णित तथ्यों के संबंध में कोई उचित अनुतोष प्रदान नहीं किया है ऐसी स्थिति में वाद प्रकरण में अन्तर्गत धारा 183 आरटीए के तहत पारित अनुतोष प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा संभलाने संबंधी तथ्य की पालना रिकार्ड में समुचित संशोधन के अभाव में अधूरा है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया। प्रकरण में हमारा यह भी विनम्र मत है कि राज० काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के तहत पारित अनुतोष के संबंध में श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्रदत्त नहीं होने से इस संबंध में किसी प्रकार के अभिमत की आवश्यकता प्रकरण में नहीं है किन्तु धारा 136 एलआरएक्ट में चाहे गये अनुतोष के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई अनुतोष अपीलार्थी को प्रदान नहीं किया है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के जेरअपील निर्णय को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। लिहाजा अपील अपीलांत आंशिक स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील निर्णय 27.6.2017 अपास्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिजा कोटा को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में सेटलमेंट से पूर्व एवं बाद के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी, खसरा गिर०, मिलान क्षेत्रफल, नक्शा लट्टा/ट्रेस आदि का समुचित परीक्षण कर रकबा बरारी करते हुये पक्षकारान को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत तथ्यात्मक निर्णय पारित करें।
- 9 निर्णय आज दिनांक 3.3.2022 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अनुराग भार्गव)
अति० संभागीय आयुक्त

कोटा